जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

चूरू

Rashtradoot

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 15 संख्याः 67 प्रभात चूरू, बुधवार 5 जुलाई, 2023 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

जब किसी प्रजाति की आबादी ज्यादा बढ़ने लगती है तो उस प्रजाति के जानवरों का आकार कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें भोजन के लिए ज्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि, कैलिफोर्निया सी लायन प्रजाति के नर इस सिद्धांत को खारिज कर रहे हैं। जर्नल करंट बायॉलजी में छपे शोध के अनुसार, चूँकि इन मरीन जानवरों को 50 साल से सरकारी संरक्षण प्राप्त है इसलिए इनकी आबादी बहुत बढ़ी है, लेकिन, नर सी लायन छोटे होने की वजाय बड़े हो रहे हैं। पचास के दशक में शिकार व प्रदूषण की वजह से कैलिफोर्निया सी लायन की आबादी में भारी कमी आ गई थी और यूनाइटेड स्टेस्ट्स में लगभग 10,000 सी लायन ही बचे थे, फिर 1972 में मरीन मैमल प्रोटैक्शन एक्ट के तहत इन्हें पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया, जिसकी वजह से बाद के दशकों में इनकी आबादी खूब बढ़ी। मरीन मैमल सैंटर के एन.जी.ओ. के अनुसार, वर्तमान में खुले समुद्र में 2.57 लाख कैलिफोर्निया सी लायन हैं एवं इन्टरनैशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर ने इस प्रजाति को ''लीस्ट कंसर्न'' वर्ग में रखा है। युनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, सैंटा क्रूज़, के शोधकर्ता और स्मिथसोनियन का नैशनल म्यूजियम नैचुरल हिस्ट्री यह जानना चाहते थे कि, इस स्तनपायी की आबादी में वृद्धि का इस जीव के आकार के लिए क्या अर्थ है। उन्होंने 1962 से 2008 के बीच एकत्रित 330 सी लायन खोपड़ियों का अध्ययन किया और पाया कि नर की खोपड़ी का आकार कुछ मिलीमीटर बढ़ा है, जिसके आधार पर इनके शरीर के आकार में लगभग 10 सैं.मी.की बढ़ोतरी कह सकते हैं। लेकिन मादा का आकार नहीं बढ़ा है। आकार बड़ा होने का मादाओं को कोई इवोल्यूश्नरी फायदा नहीं है। नर कई मादाओं के साथ जोड़ा बनाते हैं, क्षेत्र व मादा के लिए लड़ते हैं। इसलिए बड़े व ताकतवर नर को बड़े आकार का फायदा होता है। जानवरों की हड्डियों की जांच से शोधकर्ताओं को इनके भोजन के बारे में पता लगा। उन्होंने देखा कि नर कैलिफोर्निया सी लायन के भोजन खोजने का दायरा बढ़ गया है और उनके भोजन में विविधता बढ़ गई है। शोध की सहलेखक आना वैनेज़ुएला -टोरो ने कहा कि भोजन सम्बंधी लचीले रुख की वजह से ये सब कुछ खा लेते हैं इससे इनका आकार बढ़ रहा है।

सचिन खेमे ने छः तारीख की बैठक के लिये रोचक प्रस्ताव दिया

प्रस्ताव है; चुनाव के लिये राजस्थान को दो बराबर भागों में बांट दिया जाये, पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान

- पूर्वी राजस्थान की जिम्मेवारी सचिन पायलट को दी जाये तथा पश्चिमी राजस्थान की गहलोत को। दोनों हिस्सों को बराबर करने के लिये अलवर संभाग की 12 सीटों की जिम्मेवारी भंवर जितेन्द्र सिंह को।
- उन कुछ ''मस्ट सीटों'' पर, जहाँ दोनों खेमे अपना उम्मीदवार देना अति आवश्यक मानते हैं, उन सीटों का निर्णय हाई कमान पर छोड़ा जाये।
- जो व्यक्ति अधिकतम सीटें जिता कर लायेगा, वह मु.मंत्री बनेगा।
- यह प्रस्ताव दोनों खेमों के साथ न्याय तो करता ही है, साथ ही, चुनाव के बाद मु.मंत्री पद के लिये रस्साकशी की संभावना भी कम हो जाती है। जैसा छत्तीसगढ़ में बघेल व टी.एस. सिंहदेव के बीच होने की आशंका है।
- गहलोत की 6 जुलाई की बैठक में ज़ूम के मार्फत शरीक होने की बात है। पर, गहलोत के बारे में कुछ भी निश्चितता से कहना मुश्किल है। येन-केन-प्रकारेण वे राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक संकट का समाधान टालने के इच्छुक रहे हैं। जिससे वर्तमान स्थिति यथावत् बरकरार रहे। इसके लिए वे येन-केन-प्रकारेण हर बार दिल्ली जाना टालते रहे हैं।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जुलाई। राजस्थान पर चर्चा के लिये प्रस्तावित अगली मीटिंग 6 जुलाई को होगी। आशा की जा रही है कि इस मीटिंग में कोई समग्र एवं निर्णायक फॉर्मूला उभर कर आयेगा, जिससे अनिश्चितता का माहौल समाप्त हो जायेगा।

सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से भेंट करने की कोई जरूरत नहीं महसूस कर रहे, क्योंकि रंधावा सार्वजनिक रूप से अशोक गहलोत के पक्ष में अपना इकतरफा रूख व्यक्त कर चुके हैं, इसलिये ऐसा समझा जाता है कि एस.सी./एस.टी. चेयरमैन खिलाड़ी लाल बैरवा, जो सचिन की टीम का हिस्सा है, ने डोटासरा एवं रंधावा के साथ मीटिंग की थी।

इसके बाद, डोटासरा तथा रंधावा ने के.सी. वेणु गोपाल के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने, उन्हें प्राप्त हुई विभिन्न जानकारियों पर चर्चा की।

उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि, टीम सचिन ने एक महत्वपूर्ण सुझाव आगे बढ़ाया, जिसके अनुसार, राजस्थान को बीचोंबीच से दो हिस्सों में बांट दिया जाये, पश्चिमी राजस्थान की सीटों की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दे दी जाये तथा पूर्वी राजस्थान के प्रभारी सचिन पायलट बना दिये जायें।

और अलवर क्षेत्र की 12 सीटों की जिम्मेदारी भंवर जितेन्द्र सिंह को दे जी जाये। ऐसा इसलिये नहीं किया जाये कि भंवर में इन सीटों को जिताने की क्षमता है, बल्कि इसके पीछे इस प्रस्ताव को संतुलित रखने का विचार है तथा इसका दूसरा कारण यह भी है कि, भंवर जितेन्द्र सिंह गांधी परिवार के नजदीक हैं।

यह प्रस्ताव कहता है कि जो नेता ज्यादा सीटें जीत लेगा, वह चुनावों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा ने नीतीश कुमार को ''फीलर'' भेजा हरवंश के मार्फत

नीतीश ने प्रस्ताव स्वीकार न करना राजनीति की दृष्टि से ज्यादा लाभकारी समझा

- हरवंश, वैसे तो जद (यू) के राज्यसभा सदस्य हैं, पर आजकल भाजपा के ज्यादा नज़दीक हैं।
- हरवंश ने नीतीश को याद दिलाया कि, वे कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते और अब जब उप मु.मंत्री तेजस्वी यादव को सी.बी.आई. ने ''लैण्ड फॉर जॉब'' प्रकरण में भ्रष्टाचार का आरोपी बताया है, तो वे आर.जे.डी. से गठबंधन को कैसे जायज़ ठहरायेंगे।
- पर नीतीश इस तर्क से प्रभवित नहीं हुए व प्रस्ताव ठुकरा दिया। नीतीश का आकलन शायद यह है कि, आज तेजस्वी यादव बिहार में ''यूथ ऑइकॉन'' हैं और उन पर आरोप लगाना भाजपा को भारी पड़ेगा, अतः आर.जे.डी. के साथ गठबंधन बनाये रखना ही राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा लाभकारी रहेगा।

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जुलाई। ऐसी संभावना नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आर.जे.डी. (राष्ट्रीय जनता दल) से संबंध तोड़कर, फिर से एन.डी.ए. (नैशनल डैमोक्रेटिक एलायंस) में शामिल होने के भाजपा के प्रलोभन को स्वीकार कर लेंगे। सी.बी.आई. द्वारा बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ''लैंड-फॉर-जॉब्स'' केस में नामजद कर दिये जाने के बाद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने आज कुमार से उनके पटना-स्थित आवास पर भेंट की। इस भेंट के फलस्वरूप, ऐसी अटकलें लगाई जाने लगीं कि कुमार को एक बार फिर एन.डी.ए. में शामिल होने के लिये तैयार करने की कोशिश की जा रही है। समझा जाता है कि हरिवंश, जो जे.डी. (यू.) कोटा से राज्यसभा सदस्य हैं, ने भाजपा को गले लगा लिया है। पिछले अगस्त में, जब कुमार ने भाजपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया था, उसके बाद, कुमार ने हरिवंश से यह कहने की कोई पहल नहीं की कि वे राज्यसभा के उपसभापति से इस्तीफा दे दें। हो सकता है कि इसके पीछे यह विचार रहा हो कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत का एक रास्ता खुला रहने दिया जाये। इस प्रकार की अटकलें हैं कि हरिवंश की कुमार के साथ हुई इस मीटिंग का उद्देश्य बिहार के मुख्यमंत्री तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का राजनैतिक संदेश पहुँचाना रहा हो।

कुमार भ्रष्टाचार के आरोपियों के प्रति ''ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी'' रखने के लिये जाने जाते रहे हैं। 2005 में, उन्होंने उस समय जीतनराम माँझी को इस्तीफा देने के लिए कह दिया था, जब उनका नाम ''डिग्री घोटाले'' में आ गया था। इसी प्रकार, नीतीश कुमार ने 2008 में अपनी सरकार के एक अन्य मंत्री रामानन्द सिंह से उस समय इस्तीफा ले लिया था, जब उनका नाम भ्रष्टाचार के एक पुराने केस में आ गया था, जो एक थर्मल पावर स्टेशन पर घटिया किस्म के पाइप की खरीद से संबंधित था। वर्ष 2011 में कुमार ने उस समय एक और मंत्री रामधारी सिंह को बर्खास्त कर दिया था, जब वे दंगों से जुड़े एक केस में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मंत्री बालाजी के केस में सुप्रीम कोर्ट का मद्रास हाई कोर्ट को निर्देश

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जुलाई। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि, वह तमिलनाडू के गिरफ्तार मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को ''यथाशीघ्र'' तीन जजों की बैंच के समक्ष रखे। ज्ञातव्य है कि दिन में ही विभाजित

- सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि, गिरफ्तार मंत्री बालाजी के केस में शीघ्रताशीघ्र फैसला किया जाए।

फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा दीपांकर दत्ता की बैंच ने मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से यह भी कहा कि, नई बैंच बालाजी की याचिका पर अविलम्ब निर्णय दे।

मंगलवार को सुबह के समय, मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजनल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'अगर दोनों पार्टी मिल कर चुनाव लड़ेंगी तो, वोटों का विभाजन रूकेगा'

जनता दल (एस) व भाजपा कर्नाटक में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगी?

- जद (एस) के नेता कुमारस्वामी व भाजपा के येद्दियुरप्पा ने इस रणनीति पर सहमति व्यक्त की।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जुलाई। महाराष्ट्र की व्यवस्था करने और बिहार में ऐसे ही ऑपरेशन लोटस की चर्चा के बीच भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में अपनी संभावना बढ़ाने में लगी है, जहां 2019 में उसने स्वीप किया था।

महाराष्ट्र में शिव सेना के बाद भाजपा ने एन.सी.पी. में भी विभाजन कर दिये, जिससे महाविकास अघाड़ी कमजोर हुआ है और भाजपा के चुनाव जीतने की संभावना नहीं है। सूत्रों का कहना है कि बिहार में भी ऐसे ही प्रयास हो रहे हैं जहां जनता दल (यू) और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर भाजपा को गत चुनाव में जीती गई सीटों पर उसे हरा सकते हैं।

कर्नाटक में 2024 में अपनी सीटें बरकरार रखने और बढ़ाने के लिये भाजपा कर्नाटक की क्षेत्रीय पार्टी जनता दल (सैकुलर) के साथ गठबंधन करेगी ताकि दोनों पार्टियों को मिलाकर वोट कांग्रेस को हराने के लिये काफी होगा जो विधानसभा में भारी बहुमत से जीती थी।

इस बात के काफी संकेत हैं कि भाजपा और जनता दल (एस) लोकसभा चुनाव साथ लड़ेंगे।

भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता बी.एस. येदियुरप्पा ने घोषणा की कि भाजपा और जनता दल (एस) मिलकर कांग्रेस से लड़ेंगे।

दरअसल येदियुरप्पा ने जनता दल (एस) नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी के कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप का समर्थन किया और कहा कि कुमारस्वामी भ्रष्टाचार पर जो कुछ कह रहे हैं वह सही है। उन्होंने इसका समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए भाजपा जनता दल (एस) का समर्थन लेगी।

कुमारस्वामी को जिम्मेवार राजनीतिज्ञ बताते हुए येदियुरप्पा ने संकेत दिया कि दोनों पार्टियाँ मिलकर गत आम चुनाव जितनी सीटें जीत लेंगी।

लेकिन जनता दल (एस) 6 सीटों से लड़ने की सोच रहा है जहां उसे अपनी बेहतर संभावनाएं नज़र आती है। उसके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'दिव्यांग अफसरों की नियुक्ति कैसे हो रही है?'

जयपुर, 4 जुलाई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने दिव्यांग अफसरों की पोस्टिंग नीति के विरूद्ध उनके गृह जिले से बाहर नियुक्ति किये जाने से संबंधित मामले पर दायर रिट याचिका पर न्यायाधीश सुदेश बंसल ने राज्य सरकार के संबंधित विभाग को जवाब तलब किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता विजेन्द्र

- हाई कोर्ट ने दिव्यांग अफसरों को उनके गृह जिले में नियुक्ति देने की नीति के उल्लंघन पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किये।

कुमार गुर्जर व अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अरविन्द कुमार शर्मा पैरवी के लिये पेश हुए थे।

याचिकाकर्ता के अनुसार ''चीफ कमिश्नर फोर पर्सन्स विद् डिसेबिलिटीज'' यानी दिव्यांग लोगों के लिये काम करने की नीति तय करने वाले केंद्रीय विभाग और राज्य सरकार के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बुधवार को शरद पवार व अजीत पवार ने अपने-अपने समर्थकों का सम्मेलन बुलाया

शरद पवार के समर्थक, नरिमन पॉइन्ट स्थित यशवंत राव चव्हाण ऑडिटोरियम में मिलेंगे, अजीत पवार ने अपने खेमे को बांद्रा में बुलाया है

- पर अजीबोगरीब बात है कि, अभी तक दोनों खेमों ने विधानसभाध्यक्ष को अपने समर्थक विधायकों की सूची नहीं भेजी है। दोनों खेमे पूरी पार्टी पर अपना कब्जा जता रहे हैं।
- अजीत पवार ने 53 एन.सी.पी. विधायकों में से 42 विधायकों का समर्थन प्राप्त होने का दावा किया था, पर, जब उन्होंने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली, केवल आठ विधायक उनके साथ आये और वे सभी मंत्री बनाये गये।
- शरद पवार, वो गल्ती नहीं दोहराना चाहते, जो उद्धव ठाकरे ने की थी। उद्धव ठाकरे ने सभी बागी विधायकों को पार्टी से निकाल दिया था तथा इस प्रकार उन विधायकों का वापस आने का रास्ता बंद कर दिया था।
- शरद पवार ने उन विधायकों को तो पार्टी से निकाल दिया, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, क्योंकि, उनके वापस आने का कोई ''चाँस'' नहीं है, पर बाकी ''बागी'' विधायकों को मैसेज दिया है कि, घर वापसी पर उनका स्वागत होगा।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जुलाई। संकटग्रस्त नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एन.सी.पी.) के दोनों धड़ों ने बुधवार को बड़ी बैठकें बुलाई हैं ताकि अपनी संख्या सुनिश्चित कर अपने विधायकों को साथ रख सकें, लेकिन पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने पार्टी को पुनर्गठित करने के लिए जनता के पास जाने का निर्णय लिया है।

महाराष्ट्र के नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने जहां विधायकों, जिला अध्यक्षों एवं क्षेत्रीय प्रमुखों को सुबह 11 बजे मुंबई के बांद्रा में बुलाया है, वहीं पार्टी के संस्थापक और अजीत के चाचा शरद पवार ने सभी पार्टी नेताओं को दोपहर एक बजे मुंबई के नरीमन पॉइन्ट स्थित यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम में बुलाया है।

अजीत पवार खेमे का दावा है कि शरद पवार से अलग होने और महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने में उसके साथ एन.सी.पी. के 53 में से 42 विधायकों का समर्थन है। लेकिन कहा जा रहा है कि कई विधायकों ने कागज देखें बिना ही हस्ताक्षर कर दिए थे।

अजीत पवार ने 53 में 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है, लेकिन आठ विधायकों के साथ शपथ लेने के दो दिन बाद तक यह स्पष्ट नहीं है कि कौनसा धड़ा बड़ा है।

शरद पवार खेमे ने अभी तक कोई आंकड़ा नहीं बताया है। लेकिन नेताओं का दावा है कि पार्टी छोड़ने वाले कम हैं और पार्टी मजबूती से अपने नेता के साथ खड़ी है।

शरद पवार समर्थन जुटाने के लिए 8 जुलाई से नासिक से राज्य का दौरा आरंभ करेंगे।

शरद पवार पुणे, शोलापुर, नासिक, बीड़ तथा विदर्भ क्षेत्र के कुछ हिस्सों का दौरा करेंगे जो छगन भुजबल, धनंजय मुंडम और अन्य बागी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रदेश अध्यक्षों में बदलाव कर भाजपा ने चुनाव तैयारी शुरू की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने इस वर्ष के अंत में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा

- भाजपा ने पंजाब, झारखंड, आंध्र व तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। पंजाब में सुनील जाखड़, झारखंड में बाबूलाल मरांडी, आंध्र में पी. पुरंदरेश्वरी व तेलंगाना में जी. किशन रेड्डी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।

चुनावों व उसके बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सबसे पहले तो प्रदेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)